जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

कोटा

Rashtradoot

फोनः- 2386031, 2386032 फैक्सः- 0744-2386033 वर्षः 50 संख्याः 341 प्रभात कोटा, बुधवार 24 सितम्बर, 2025 कोटा/24/2012-14 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

विश्वास नहीं जम पा रहा, भारतीय प्रोफैशनल्स का ट्रंप की "इमिग्रेशन" नीतियों पर

नवीनतम नीति के अनुसार, अमेरिका उन विदेशी प्रोफैशनल्स को प्राथमिकता देगा, जिनका वेतन भारी है और शैक्षणिक योग्यता भी अधिक है

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 सितंबर।

न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के भाषण ने यह भरोसा नहीं दिलाया कि अमेरिका एच-1बी वीज़ा रखने वाले भारतीय प्रवासियों का स्वागत करेगा। इसके बजाय यह धारणा और मजबूत हुई कि यह राष्ट्रपति अमेरिका में विदेशी कामगारों की मौजूदगी को सीमित करने पर तुला हुआ है।

ट्रंप प्रशासन ने अचानक ही हर एच-1बी वीज़ा आवेदक पर प्रति वर्ष 1,00,000 डॉलर की भारी फीस लगाने की घोषणा कर दी। व्यापक विरोध के बाद सरकार ने सफाई दी कि बढ़ी हुई वीज़ा फीस सिर्फ नए आवेदकों पर लागू होगी और वर्तमान वीज़ा धारकों को बिना किसी रुकावट के काम जारी रखने दिया जाएगा।

- अब तक एच-1बी वीज़ा, लॉटरी सिस्टम से दिया जाता था, जिसमें कम या भारी तनख्वाह पाने वालों को एक ही पलड़े में रखा जाता था, लॉटरी निकालने से पहले।
- यूनएन की 80वीं जनरल असैम्बली को संबोधित करते हुए, ट्रंप ने विदेशी प्रोफैशनल्स को वीज़ा देने की नई नीति को उजागर किया।
- ट्रंप ने अपने भाषण में यूरोपीय देशों की भी काफी आलोचना की, कि इन देशों ने गैर-कानूनी तरीके से सीमा पार से आने वाले वर्कर्स की समस्या पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया और इसीलिए ये यूरोपीय देश भारी संकट में हैं।
- भारतीय आईटी प्रोफैशनल्स व अमेरिका की बड़ी-बड़ी आईटी कम्पनियां, आपस में पूर्णतया सहयोग कर रही हैं, ट्रंप की नित्य, रोज-रोज बदलती नीतियों के साथ एडजस्ट करने के लिए। जितना आवश्यक भारतीय आईटी प्रोफैशनल्स के लिए अमेरिका में नौकरी मिलना है, उतना जरूरी अमेरिका की आईटी कम्पनियों के लिए भारतीय वर्कर्स को नौकरी देना है, क्योंकि अगर विदेशी आईटी प्रोफैशनल्स नहीं हों तो इस सैक्टर के लिए अमेरिका में जीवित रहना उतना ही मुश्किल हो जायेगा।

आज ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीज़ा के आवंटन की एक नई प्रणाली की भी घोषणा की, जिसमें आवेदकों के वेतन और शैक्षिक योग्यता को जोड़ा जाएगा। नई योजना के तहत अब वीज़ा लॉटरी प्रणाली से नहीं दिए जाएंगे, बल्कि अब ऊँचे वेतन वाली नौकरियों और अधिक शिक्षा प्राप्त उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलेगी।

इरादा यह है कि केवल बहुत ऊँचे वेतन वाले पदों पर कार्यरत लोगों की ही इन वीज़ाओं तक आसान पहुँच मिले

(शेष पृष्ठ 5 पर)

आरपीएससी में तीन सदस्य नियुक्त

अजमेर, 23 सितम्बर। राजस्थान लोक सेवा आयोग में तीन नये सदस्य नियुक्त किए गये हैं। पूर्व आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी के अलावा, डॉ. सुशील कुमार बिस्सू व डॉ. अशोक कुमार कलवार सदस्य बने हैं।

- पूर्व आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी, कैंसर स्पेशलिस्ट डॉ. अशोक कलवार तथा शिक्षाविद् डॉ. सुशील कुमार बिस्सू सदस्य बने।

आयोग में अभी छह सदस्यों के पद खाली चल रहे थे। अब तीन नये सदस्यों की नियुक्ति होने के बाद, आयोग सदस्य के दस में से सात पद भर गये हैं, पर तीन पद अब भी खाली हैं। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में राजस्थान लोक सेवा आयोग में यह दूसरी नियुक्ति है। इससे पहले, पूर्व डीजीपी यूआर साहू को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। हेमंत

(शेष पृष्ठ 5 पर)

राहुल गांधी की "यात्रा" ज्यादा रास नहीं आ रही आरजेडी को

आरजेडी का मानना है, यात्रा ज्यादा सफल हुई तो कांग्रेस और अधिक सीटें मांगेगी और इससे तेजस्वी को मु.मंत्री बनाने की कोशिश में दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 सितंबर। प्रतीकात्मक रूप से यह अवसर बहुत बड़ा है, 1940 के बाद यह पहला अवसर है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) की विस्तारित बैठक को बुधवार को पटना के सदाकत आश्रम स्थित पार्टी मुख्यालय में हो रही है। राहुल गांधी की हालिया "वोट अधिकार यात्रा" की पृष्ठभूमि में, कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारण संस्था सीडब्ल्यूसी की इस ऐतिहासिक स्थल पर बैठक नवंबर में होने वाले चुनावों को लेकर पार्टी के उत्साह का संकेत मानी जा रही है।

वस्तुतः यह बड़ा आयोजन एक राजनीतिक दबाव के तरीके के और कुछ नहीं माना जाना चाहिए, जिसका उद्देश्य लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के साथ सीटों के बंटवारे में अधिकतम और जिताऊ सीटें हासिल करने का अप्रत्यक्ष प्रयास है।

- उदाहरण के लिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 70 टिकट देने पड़े थे, महागठबंधन को, पर, कांग्रेस जीती केवल 19 सीटों पर।
- कांग्रेस का जवाबी तर्क है, उसे अधिकतर वो सीटें दी गई थीं, जिन पर महागठबंधन का जीतना असंभव था। अतः इस बार कांग्रेस का ख्वाब है, चाहे पाँच-सात टिकट कम मिलें, पर वो सीटें मिलें जहाँ वह मजबूत है और जीत सकती है।
- बहरहाल, शायद अभी कांग्रेस व आरजेडी अपने-अपने रास्ते पर अलग-अलग चल रहे हैं।

महागठबंधन की उभरती राजनीतिक बारीकियाँ इसकी सूक्ष्म

(शेष पृष्ठ 5 पर)

ट्रंप का "वीज़ा खेल" : भारत को शॉर्ट-टर्म परेशानी, पर अमेरिका को दीर्घकालीन नुकसान

इकॉनमिस्ट, अमेरिका की ग्रोथ को 2 प्रतिशत से घटाकर 1.5 प्रतिशत रहने की आशंका जता रहे हैं

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 सितम्बर। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का अचानक एच-1बी वीज़ा पर 1,00,000 डॉलर की भारी फीस लगाने का फैसला फिलहाल भारतीय टैक कर्मचारियों को झटका दे सकता है, लेकिन असली बड़ा नुकसान अमेरिका को होने का अंदेशा है। भारत, जहां एच-1बी वीज़ा धारकों की सबसे बड़ी संख्या है, को शुरुआती परेशानी ज़रूर होगी, पर अर्थशास्त्री चेतावनी दे रहे हैं कि इससे अमेरिका को अपनी आर्थिक वृद्धि में रुकावट आने का खतरा है, टैक्नॉलजी में उसकी प्रतिस्पर्धा कमज़ोर हो सकती है और सिलिकॉन वैली के अलावा भी, कई क्षेत्रों को नुकसान पहुँच सकता है। सप्ताहांत में हुई इस घोषणा ने अमेरिका की टैक्नॉलजी दुनिया में अफरा-तफरी मचा दी। विदेशी कर्मचारी देश से बाहर फँस जाने के डर से उड़ानों की तलाश में जुट गए, जबकि सिलिकॉन वैली की कंपनियों ने कर्मचारियों को यात्रा न करने की सलाह दी। कुछ घंटों में ही वाइट हाउस को सफाई देनी पड़ी कि यह फीस सिर्फ नए वीज़ा आवेदनों पर लगेगी और वह भी एक बार की होगी।

- दूसरी ओर, भारत की विशाल जानी-मानी आईटी कंपनियाँ, भारत के आईटी उद्योग टैरिफ से उत्पन्न होने वाली दिक्कतों का सामना करने के लिए काफी समय से तैयारियाँ कर रही थीं।
- उदाहरण के लिए, इन कंपनियों ने अमेरिका में ही स्थानीय वर्क फोर्स तैयार कर ली थी। अतः भारत तत्कालिक पीड़ा को, नई बिजनैस रणनीति, डिलिवरी मॉडल में तब्दीलियाँ करके बर्दाश्त कर लेगा।

(शेष पृष्ठ 5 पर)